

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1972/2013/उदयपुर

सहायक आयुक्त

वृत बी, उदयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शिल्पा ट्रेडलिंग प्रा.लि.

उदयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के. अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री राकेश मेहता

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 25.03.2015

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, वृत-बी, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 113//वैट/2012-13/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत आलोच्य अवधि 2009-10 का कर निर्धारण आदेश 13.08.2012 को पारित कर अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 48 की पूर्ति नहीं करने के कारण अर्थात् बिना नोटिस जारी किये ही आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2013 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तिमाही रिटर्न देशी से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा रेकार्ड एवं प्रकरण के तथ्यों को नरजन्दाज कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो अविधिक है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि कर एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व कर निर्धारण

अधिकारी द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए आरोपित शास्ति नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। उनका कथन है कि नियम नियम 48 की पालना नहीं की गई है, इसलिए आरोपित कर एवं शास्ति अविधिक है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीले अस्वीकार करने का निवेदन किया।।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने द्वारा कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एवं विशिष्ट नोटिस दिये बिना अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है, जो नियम 48 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 65 एवं नियम 48 को उद्धृत किया जाना समीचीन है, जो इस प्रकार है :-

"65. Opportunity before imposition of penalty. – No penalty under this Act shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the dealer or the person concerned."

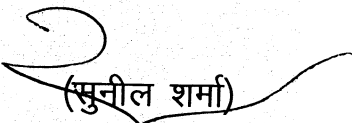
नियम 48 निम्न प्रकार है :-

"48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,- Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard."

अधिनियम एवं नियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने से पूर्व व्यवसायी को विशिष्ट नोटिस दिया जाना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना विधिक रूप से आवश्यक है, जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उपरोक्त प्रावधानों एवं राजस्थान सेल्स टैक्स अधिकरण एवं कर बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णयों को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2013 में उद्धृत करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2013 को यथावत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य